शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

कांग्रेस ने दिया ज्ञापन

'लाखों छात्र व शिक्षकों पर मंडरा रहा खतरा'

इंदौर. कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण के चलते रुकी परीक्षा जून की जगह जुलाई में कराने की मांग को लेकर आंचलिक कार्यालय पर ज्ञापन दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक खंडेलवाल, सेवादल अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में आंचलिक अधिकारी देवेंद्र सोनवानी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया, मप्र शासन ने कक्षा 12वीं के शेष पेपरों की परीक्षा 9 जून से कराने का निर्णय लिया। ऐसे समय में लाखों विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालकर परीक्षा केंद्रों पर जाना होगा। हजारों शिक्षक के लिए भी जोखिम ही रहेगा।

प्रशासन के आदेश के अनुसार रखेंगे व्यवस्था

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए पालक के साथ ही संचालक भी सचेत

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. शहर के शासकीय व निजी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर जहां स्कूल संचालक परेशान हैं वहीं पालक भी सचेत हैं। फिलहाल पालक बच्चों को अगले दो माह तक स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं हैं। वहीं स्कूल भी ऑनलाइन कक्षाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

जुलाई से स्कूल शुरू होना हैं। इसे लेकर अभी से निजी के साथ ही शासकीय स्कूलों में कसरत शुरू हो गई है। पालक के साथ ही स्कूल संचालक भी चितिंत हैं। लेकिन शासन-प्रशासन के निर्देशों का इंतजार हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन करने को स्कूल संचालक तैयार है। फिलहाल तो निजी स्कूल जहां ऑनलाइन कक्षाओं पर ध्यान केंद्रीत कर रहे है वहीं शासकीय स्कूलों में भी सोशल मीडिया व आकाशवाणी के साथ दूरदर्शन के माध्यम से क्लास लगाई जा रही है। 30 मई तक क्लास जारी रहेगी।

नहीं भेजेंगे स्कूल

- एयरपोर्ट निवासी वंदना वर्मा ने बताया, कोरोना के चलते अभी तो बच्चों को स्कूल भेजने की सवाल ही नहीं उठता है। भले ही स्कूल में बच्चे कम हों और पूरी सतर्कता रखी जाए लेकिन मामला गंभीर है। दीपावली बाद ही सोचेंगे।
- बंगाली चौराहा निवासी शालू जोशी ने कहा, महामारी में बचाव ज्यादा जरूरी है। बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं रखा पाएंगे। फिलहाल तो उन्हें स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। संक्रमण खत्म होगा तभी भेजेंगे।

स्कूल जुलाई में खुलेंगे और उसके बाद पढ़ाई करवाएंगे। संक्रमण को लेकर जितने दिन स्कूल लगेगा और जितना कोर्स होगा उसी में से परीक्षा लेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए एक्सट्रा क्लासेस भी लगाई जा सकती है।

पंकज संघवी, गुजराती स्कूल ट्रस्टी

शासकीय स्कूलों में एक जैसी व्यवस्था होगी। जैसे आदेश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। अभी आकाशवाणी व दूरदर्शन से बच्चों की कक्षा चल रही है।

राजेंद्र मकवानी, जिला शिक्षा अधिकारी

स्कूल खुलने पर हर बच्चे की स्क्रीनिंग, बच्चे और शिक्षक दो शिफ्ट में आएंगे

रायसेन. हालांकि अभी स्कूल खुलने का कोई निर्णय शासन स्तर पर नहीं हुआ है। मगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल खोले जाने को लेकर बनाई जा रही योजना को देखते हुए निजी और सरकारी स्कूलों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच सरकारी आदेशों के अलावा भी स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर सुरक्षा के विभिन्न उपायों को लेकर योजना बनाने लगे हैं।

हालांकि इसमें सरकारी स्कूलों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक होती है, जबकि उनके मुताबिक बैठक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प भी खुला हुआ है। जिस पर सरकारी स्कूलों में पहले से ही काम जारी है। स्कूल खुलने पर व्यवस्थाएं जुटाना खासी परेशानी भरा होगा। ऐसे में बच्चों को दो शिफ्टों में बुलाने के अलावा एक कक्षा के दो या अधिक बैच बनाकर अलग-अलग समय में बुलाने के विकल्प पर भी विचार-विमर्श जारी है।

नगर के शाइनिंग पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल के संचालक सत्येंद्र सिंह राणा ने बताया कि हम शासन के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। हमने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राणा ने बताया कि उन्होंने तय किया है कि नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू नहीं करेंगे।

31 मई तक कर सकते हैं आवेदन

सीएसआईआर यूजीसी नेट में आवेदन करने पर मिली राहत

भोपाल ◆ कोविड-19 की वजह से परेशानी को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सीएसआईआर (काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च) यूजीसी नेट में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। एनटीए के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी छात्र को अब तक आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त हो सका है, तो वह इस सर्टिफिकेट को बिना अपलोड किए ही सीएसआईआर-यूजीसी-नेट के लिए आवेदन कर सकता है।

दरअसल, आरक्षित श्रेणी से संबंधित छात्रों को यूजीसी-नेट का आवेदन करने के लिए श्रेणी का प्रमाणपत्र अपलोड करना पड़ता है। लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है। ऐसी स्थिति में उनके लिए सर्टिफिकेट बनवाना मुश्किल है। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनटीए से अनुरोध किया था कि इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए एनटीए यूजीसी-नेट करने के इच्छुक छात्रों के लिए अनिवार्य सर्टिफिकेट अपलोड करने की व्यवस्था को खत्म करें। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है।

ट्वीट कर दी जानकारी

निशंक ने ट्वीट किया कि यूजीसी-नेट देने के इच्छुक प्रिय छात्र। लॉकडाउन के कारण आपकी कठिनाइयों को देखते हुए हमने एनटीए को सलाह दी है कि इस परीक्षा के लिए आवेदन के दौरान फोटोग्राफ और सिग्नेचर के अलावा किसी अन्य चीज को अपलोड करने की अनिवार्यता न रखें। अंतिम परीक्षा का परिणाम भी यदि नहीं आया है, तो इसकी भी छूट दी जाए। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र बाद में सुविधानुसार जमा करना अनिवार्य होगा। छात्र अब 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं।

एनसीईआरटी कर रहा सिस्टम तैयार

सीबीएसई स्कूलों में अपनाया जा सकता है ऑड इवन फॉर्मूला

भोपाल ♦ कोरोना वायरस का असर स्कूल परिसर के साथ क्लास रूम में भी दिखेगा। स्कूलों में भी वाहन की तरह ऑड-इवेन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। नए नियम के तहत ऑड रोल नंबर वाले बच्चे एक दिन तो इवेन रोल नंबर वाले बच्चे दूसरे दिन स्कूल आएंगे। यानी अब छात्र-छात्राएं रोज स्कूल नहीं आ पाएंगे। यह इसलिए ताकि क्लास रूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

ज्ञात हो कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देश के बाद सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लॉकडाउन के बाद स्कूल में बच्चों के आने का सिस्टम कैसा होगा। इसको लेकर एनसीईआरटी और स्कूल स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। एक दिन करके बच्चों को बुलाने से शिक्षकों पर कोर्स पूरा करने का दबाव रहेगा। ऐसे में

शिक्षकों की ड्यूटी अधिक बढ़ जाएगी। जो बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं आएंगे, उनकी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। इसके लिए संबंधित शिक्षक क्लास रूम पढ़ाई को छात्रों को भेजेंगे।

ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था

स्कूलों में ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। रोज बच्चों को स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। अगर किसी भी बच्चों को जुकाम या सर्दी की शिकायत हुई तो उन्हें तुरंत घर वापस भेज दिया जोगा।

बाल आयोग ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र

150 शिकायतें थीं, केवल दो स्कूलों को दिया नोटिस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. लॉकडाउन अवधि में केवल ट्यूशन फीस लिए जाने के सम्बंध में आदेश जारी हो जाने के बाद भी कई स्कूल कई मदों की फीस ट्यूशन फीस में जोड़कर भारी-भरकम राशि अभिभावकों से वसूलने में लगे हैं। इस मामले में आदेश जारी होने के बाद से 150 से ज्यादा शिकायतें बाल संरक्षण आयोग के पास पहुंच चुकी हैं। आयोग की दो बार की अनुशंसा और फिर सख्ती दिखाने के बाद आखिरकार बुधवार को दो स्कूलों को नोटिस जारी किए। मामूली कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए आयोग ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सरकार के निर्देश न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है।

राज्य सरकार की ओर से निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कई स्कूल ट्यूशन फीस के साथ वार्षिक फीस जोड़कर वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा फीस नियंत्रण आदेश से पहले ही तिमाही की पूरी फीस वसूल चुके स्कूल भी

वसूली हुई फीस समायोजित नहीं कर रहे थे। निजी स्कूलों की मनमानी की 150 से अधिक शिकायतें बाल आयोग के पास पहुंची थी। जिसके बाद बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर फिर अनुशंसा करने के साथ सख्ती दिखाई तो आखिर में दो स्कूलों के प्रबंधन को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ स्कूलों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बीच चौहान ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर फीस समायोजित करने एवं शासन के अनुसार केवल ट्यूशन फीस वसूले जाने के सम्बंध में अनुशंसा की है।

अभिभावक संघ कलेक्टर से मिला

डीइओ से बोले कलेक्टर-मनमानी करने वाले स्कूलों को भेजो नोटिस

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सतना. निजी स्कूल संचालकों की मनमानी रोकने कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को अभिभावक संघ ने कलेक्टर से मुलाकात कर निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों पर दबाव बनाकर की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने डीइओ से फोन पर चर्चा की और अभिभावकों पर फीस जमा करने व किताब खरीदने के लिए दबाव बनाने वाले निजी स्कूलों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस भेजने एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अभिभावक संघ ने रखी तीन मांग

अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की। संघ ने कहा कि शहर कि सभी निजी स्कूलों की अपनी स्टेशनरी दुकान हैं। जहां पर निजी प्रकाशकों की किताबें अभिभावकों को मनमानी दाम पर बेची जाती हैं। लॉकडाउन के कारण फीस जमा करने की छूट के बावजूद निजी स्कूल मैसेज कर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं, यह उचित नहीं हैं। कलेक्टर से मुलाकात करने वालों में अभिभावक संघ के अध्यक्ष विजय देवसेना, संरक्षक गुलाब सोनी, राजललन सिंह, राकेश श्रीवास्तव, नीतू मिश्रा व माया गौतम शामिल रहीं।

कलेक्टर ने कहा, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए केंद्रीय समिति ने गाइडलाइन जारी की है। कोई भी स्कूल छात्र व अभिभावको को स्कूल या किसी दुकान से किताब खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि शहर के निजी स्कूल संचालक ऐसा कर रहे है तो यह गंभीर मामला है। अभिभावको से स्कूल फीस एवं पुस्तकों की रसीद इकट्ठा कर निजी विद्यालयो को नोटिस जारी किया जाएगा।

उत्तराखंड हाईकोर्ट

निजी स्कूलों को फीस वसूली पर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. उत्तराखंड में ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस वसूली करने पर प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने 12 मई को एक याचिका पर आदेश जारी कर ई-मेल, वाट्सऐप, फोन से फीस मांगने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों का एक संगठन प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

ट्यूशन फीस ले रहे या पूरी फीस, बताने तैयार नहीं हैं निजी स्कूल

अभिभावकों पर फिक्स अमाउंट जमा करने का दबाव, डीइओ ने कहा कि शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। इस आदेश को धता बताते हुए कुछ निजी स्कूलों ने मनमानी वसूली शुरू कर दी है। कुछ निजी स्कूल अभिभावकों पर फिक्स अमाउंट जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। अभिभावकों के सामने यह स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि उन्हें ट्यूशन फीस के रूप में कितनी राशि जमा करनी होगी।

क्राईस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल में कक्षा छठवीं से आठवीं तक की फीस 3850 रुपए है। इसमें ट्यूशन फीस 2500 रुपए है। स्कूल प्रबंधन ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि केवल ट्यूशन फीस जमा करनी है। अभिभावक फीस जमा करने के लिए स्कूल के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि सेंट अलॉयशियस स्कूल ने कक्षा छठवीं से आठवीं तक के छात्रों को पहली किश्त के रूप में 5200 रुपए जमा करने का मैसेज भेजा है। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह ट्यूशन फीस है या इसमें कोई और राशि शामिल है। लिटिल वर्ल्ड स्कूल में कक्षा छठवीं से आठवीं तक की फीस 4995 रुपए है। इसमें ट्यूशन फीस 1768 रुपए है। प्रबंधन का दावा है कि केवल ट्यूशन फीस ही ली जा रही है। वहीं अभिभावकों को केवल रिवाइज फीस जमा करने के लिए मैसेज भेजा गया है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितनी फीस जमा करनी होगी। यही हालात शहर के ज्यादातर स्कूलों में हैं। जिला प्रशासन की ओर से निजी स्कूलों की निगरानी के लिए कोई भी सिस्टम तैयार नहीं किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही ली जाए।

पूरी फीस जमा करने वालों को राहत नहीं | राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिन अभिभावकों ने राज्य सरकार के आदेश जारी होने के पहले अप्रैल और मई माहों की पूरी फीस जमा कर दी है, उनकी फीस समायोजित की जाएगी। निजी स्कूलों ने अभी तक अप्रैल और मई की पूरी फीस जमा करने वाले अभिभावकों की फीस समायोजित नहीं की है। इस वजह से अभिभावक परेशान हो रहे हैं।

मनमानी फीस वसूली पर होगी कार्रवाई | जिला शिक्षा अधिकारी सुनील नेमा का कहना है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस जमा करने का आदेश दिया है। यदि कोई निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक अतिरिक्त फीस वसूली की शिकायत प्रमाण सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं।पी-2

लॉकडाउन में फंसे छात्रों को प्रेरित करने के लिए पहल

वर्जीनिया: निराश छात्रों को रिटायर्ड टीचर सिखा रहे हैं जिंदगी के सबक

छात्रों से कहते हैं- गलती स्वीकारने से मत डरो, पर उसे ठीक भी करो

एजेंसी | वर्जीनिया (अमेरिका)

अमेरिका के वर्जीनिया के छात्र कोरोना संकट के बाद भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में रिटायर्ड टीचर्स उनका हौसला बढ़ाकर उन्हें आने वाली जिंदगी और चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। इनमें 70 से लेकर 95 साल तक के टीचर्स शामिल हैं। इन्हीं में से एक हैं 91 साल की निओला वॉलर। करीब 30 साल तक मैथमैटिक्स की टीचर रहीं निओला कहती हैं- 'इन छात्रों को हमारी जरूरत है। हम इन्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे सकते हैं।' निओला को फ्रैंक डब्ल्यू कॉक्स स्कूल की छात्रा अलेक्जांड्रिया पजानो का मेंटर बनाया गया है। पजानो कहती हैं, 'उन्होंने न मुझे सामाजिक जीवन, बल्कि बेहतर कैरियर के लिए भी प्रेरित किया।' कैप्टन डेविड छात्र जॉर्डन पार्कर के मेंटर हैं। वे कहते हैं, 'अपने शौक और बचपन को जिंदा रखना। गलती स्वीकारने से मत डरो, पर उसे ठीक भी करो।' कई छात्र-टीचर्स की बॉन्डिंग तो अब जिंदगीभर के लिए हो गई है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने की एक माह तक चले डिजिलेप कार्यक्रम की समीक्षा

भास्कर संवाददाता। रीवा

शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन परियोजना इक्युप के जिला नियंत्रण केन्द्र में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई की मासिक बैठक आयोजित की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लॉकडाउन के बीच शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए डिजिलेप एवं ई-लेर्निंग कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ किए जाने पर जोर दिया। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. रामनरेश पटेल प्राचार्य पीजीडीपी प्रफुल्ल शुक्ला, डाइट प्राचार्य श्यामनारायण शर्मा, आरती श्रीवास्तव, डॉ. पीएल मिश्रा एडीपीसी रमसा, सुदामालाल गुप्ता डीपीसी के अलावा अमरनाथ सिंह एपीसी, अजय निगम एपीसी रमसा, संतोष पाण्डेय इक्यूप नियंत्रण केन्द्र प्रभारी राजेश सिंह, प्रदीप नामदेव एवं कमलेश कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। इस बैठक में बीईओ एवं बीआरसीसी की उपस्थिति अनिवार्य रही। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों में करीब एक माह तक चले इस कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम को लगातार जारी रखने और संबंधित अधिकारियों द्वारा लगातार इसकी मॉनीटरिंग किए जाने पर जोर दिया।

इन मुद्दों पर चर्चा

बैठक के दौरान विकासखण्डों में कक्षा 1 से 8 तक की विकासखण्ड श्रोत समन्वयक बीआरसीसी एवं कक्षा 9 से 12 तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखण्ड की जानकारी विद्यालयवार एवं कक्षावार ग्रुप में जुड़े छात्रों की संख्या जिनके पास दूरदर्शन, स्मार्ट फोन, मोबाइल एवं ऐसे बच्चे जिनके पास उपरोक्त कोई सुविधा नहीं है की एकजाई जानकारी तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। भोपाल से आने वाली पाठ्य सामग्री की पहुंच सभी विद्यालयों तक सुनिश्चित की जाय। कार्यक्रम की मॉनीटरिंग एवं राज्य स्तर पर जिले की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाय। शिक्षक डिजिलेप समर्थन फार्म भरे जाने की विकासखण्डवार जानकारी प्रस्तुत करेंगे। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षक प्रशिक्षण पंजीयन की स्थिति के साथ-साथ राज्य आनंद संस्थान भोपाल द्वारा संचालित कोर्स में समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पंजीयन कराए जाने पर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि इन दिनों जिले भर में राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशन पर गर्मी के दिनों में लॉकडाउन के चलते डिजिलेप कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।

आरक्षित श्रेणी का सर्टिफिकेट न होने पर भी कर सकेंगे आवेदन

यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को बड़ी राहत

कार्यालय संवाददाता | रीवा

कोविड-19 की वजह से परेशानी को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीएसआईआर (कांउसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च) यूजीसी नेट में आवेदन करने वाले क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। एनटीए के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी विद्यार्थी को अब तक आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त हो सका है, तो वह इस सर्टिफिकेट को बिना अपलोड किए ही सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर सकता है। दरअसल आरक्षित श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को यूजीसी नेट का आवेदन करने के लिए आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र अपलोड करना पड़ता है। लेकिन लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है और प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सर्टिफिकेट बनवाना काफी मुश्किल है।

अंतिम परीक्षा का प्रमाणपत्र भी नहीं मांगा जाएगा

यूजीसी नेट की परीक्षा देने के लिए आवेदक को अब आवेदन के दौरान फोटोग्राफ और सिग्नेचर के अलावा किसी अन्य चीज को अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यहां तक कि अंतिम परीक्षा का परिणाम भी यदि नहीं आया है, तो इसकी भी छूट दी गई है। हालांकि एनटीए ने यह स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को यह सभी प्रमाणपत्र बाद में सुविधानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

तीसरी बार बढ़ाई गई आवेदन की तारीख

कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन से कठिनाइयों को देखते हुए विद्यार्थी के लिए आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए एनटीए ने यह फैसला किया है कि विद्यार्थियों को कई तरह के अनिवार्य प्रावधान से तत्काल छूट प्रदान की जाए। इसमें कई तरह के अण्डर टेकिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिजल्ट अवेटेड अटेसटेशन फार्म जैसे अनिवार्य कालम को न भरने की छूट प्रदान की गई है। कहा गया है कि ये सभी दस्तावेज जब संबंधित प्राधिकार की ओर से निर्गत कर दिए जाएंगे या सीएसआईआर को आवश्यकता होगी विद्यार्थियों से मांगे जा सकते हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण सीएसआईआर यूजीसी नेट में आवेदन करने की तारीख अब 31 मई तक कर दी गई है।

निशंक बोले- बोर्ड परीक्षाओं के बाद खोले जा सकते हैं स्कूल

अंतिम फैसला जमीनी स्थिति को देखते हुए ही लिया जाएगा

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जुलाई में स्कूल खोलने की संभावना जताई है। बुधवार को एक चैनल से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लॉकडाउन के चलते पूरी नहीं हो सकी हैं। सरकार बची हुई परीक्षाएं जुलाई में आयोजित करने जा रही है। इसके बाद स्कूल छात्रों के लिए दोबारा खोले जा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अंतिम फैसला जमीनी स्थिति को देखते हुए ही लिया जाएगा। ऐसा निर्णय लेते समय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

निशंक ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे अपने गृह जिलों या अन्य प्रदेश में चले गए हैं, उन्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्हीं जिलों मे करवाने का प्रयास कर रहा है। बोर्ड ने फैसला लिया है कि ऐसे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में दे सकते हैं। छात्रों को परीक्षा देने के लिए बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ग्रामोदय में वेबीनार आज राज्यपाल देंगे व्याख्यान

स्टार समाचार | सतना

विश्वविद्यालय में आत्मनिर्भर भारत थीम पर ऑनलाइन संबोधन देगें टंडन

पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेजा, वैद्य केएस धीमान भी करेंगे शिरकत

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के वेबीनार में गुरुवार को राज्यपाल लालजी टंडन ऑनलाइन व्याख्यान देंगे। टंडन आत्मनिर्भर भारत थीम पर संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अलावा पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेजा, वैद्य केएस धीमान भी बात रखेंगे। बुधवार को आत्मनिर्भर भारत की थीम पर वेबीनारों की सीरीज में विश्वविद्यालय में हर्बल न्यूट्रिसनल सप्लीमेंट्स फॉर इम्युनिटी डेवलपमेंट अगेंस्ट कोविड-19 विषय पर नेशनल वेबिनार है। जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के बायोलॉजिकल साइंस के विद्वानों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हर्बल न्यूट्रिसनल सप्लीमेंट्स के योगदान पर विचार व्यक्त किए। गुरुवार को विश्वविद्यालय में कोविड-19 ग्रामीण स्वास्थ्य की चुनौतियों और आयुर्वेदिक समाधान विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार होगी। राज्यपाल और कुलाधिपति लालजी टंडन इसका उद्घाटन करेगें।

ये अतिथि भी करेंगे शिरकत

ग्रामोदय विश्वविद्यालय और आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र में पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेजा सचिव आयुष मंत्रालय, दीन दयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉ अभय महाजन, सीसीआरएस भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल प्रो वैद्य केएस धीमान, आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड के कुलपति प्रो अरुण कुमार त्रिपाठी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ अशोक वार्ष्णेय सम्मलित होंगे। अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो नरेश चंद्र गौतम करेगें।

12वीं का रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी

9 से 16 जून तक होगी परीक्षा

स्टार समाचार | सतना

हायर सेकेंडरी और हायर सेकंडरी व्यवसायिक परीक्षा 12 वीं की बाकी बचे विषयों की परीक्षा (सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों) के लिये परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षाऐं 9 जून से 16 जून तक पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी। वर्तमान मे नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए परीक्षा केन्द्रों पर फिजिकल डिस्टेंन्सिगं के तहत एग्जाम आयोजित करवाने के निर्देश दिए गए है।

इनके दिए गए निर्देश

- प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों को सेनेटाइज करने
- छात्रों के साथ-साथ अधिकारी कर्मचारी अपने नाक- मुह को नकाब से ढकेंगे व फिजिकल डिस्टेंन्सिग के नियम का पालन करेगे।
- केन्द्राध्यक्ष के द्वारा परीक्षा केन्द्रों मे छात्रों के साबुन से हाथ धुलने एवं हैण्डसेनेटाइजर की व्यवस्था।
- केन्द्रों मे छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी
- परीक्षा कक्ष मे छात्रों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 1 घंटे पहले पहुंचना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा-

सरकारी जमीन मुफ्त में लेने वाले अस्पताल फ्री में करें इलाज

» प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के खर्च पर लगाम लगाने की अपील पर सुनवाई

» सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी

नई दिल्ली | एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से कहा कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की पहचान करें जहां कोरोना के मरीजों को फ्री या मामूली खर्चे पर इलाज मिल सके। कोर्ट ने कहा कि जिन अस्पतालों को फ्री में या फिर बहुत कम रेट पर जमीन मिली है उन्हें कोरोना के मरीजों का इलाज भी फ्री करना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा- कई प्राइवेट अस्पताल आर्थिक शोषण कर रहे

प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना ट्रीटमेंट के खर्च पर लगाम लगाने की मांग की याचिका एडवोकेट सचिन जैन ने लगाई थी। उनका आरोप है कि कई निजी अस्पताल संकट के समय में भी कोरोना के मरीजों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। जैन का कहना है कि जो प्राइवेट अस्पताल सरकारी जमीन पर बने हैं या चैरिटेबल संस्थान की कैटेगरी में आते हैं, सरकार को उनसे कहना चाहिए कि कम से कम कोरोना के मरीजों का तो जनहित में फ्री या फिर बिना मुनाफा कमाए इलाज करें।

7 दिन बाद अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 अप्रैल को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, इस बारे में सरकार को फैसला लेना था। हम अपना जवाब पेश कर देंगे। अगली सुनवाई 7 दिन बाद होगी।

'जिन गरीबों के पास इंश्योरेंस नहीं, उन्हें भी निजी अस्पतालों में फ्री इलाज मिले'

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सरकार को ये निर्देश देने की अपील भी की है कि गरीब तबके के कोरोना पीड़ित मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाएं तो उनका खर्च सरकार उठाए। जिन गरीबों के पास कोई इंश्योरेंस कवर या आयुष्मान भारत जैसी स्कीम नहीं है उन्हें भी फ्री इलाज मिले। साथ ही जिन गरीबों के पास इंश्योरेंस कवर है, लेकिन इलाज का खर्च रिएंबर्समेंट से ज्यादा होता है तो उसकी भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए।

एक जुलाई से खुलेंगे स्कूलों के ताले

रायपुर, (एजेंसी)। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों के साथ स्कूलों और दुकानों के साथ अन्य विषयों पर भूपेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई अहम फैसले किए। मुख्यमंत्री निवास में भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालित की जाएगी। स्कूल-कॉलेजों को कैसे प्रारंभ करेंगे। इस पर नीतिगत निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि एक जुलाई से छत्तीसगढ़ में स्कूल प्रारंभ होगी, अब बाजार 6 दिन खुलेंगे। धार्मिक और राजनीति आयोजन बंद रहेंगे। शादियों के एप्लीकेशन लिए सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं, उनके लिए तहसीलदार अनुमति देंगे। रविंद्र चौबे ने कहा कि अभी भी छत्तीसगढ़ में 40 से 50 हजार प्रवासी श्रमिक आएंगे। ऐसी स्थिति में क्वारेंटाइन सेंटर में और कितनी व्यवस्था बेहतर की जा सकती है, टेस्टिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार किया गया है।

सरकार के वित्तीय कटौती के सवाल पर उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से अनुमति लेने के बाद ही विभागों में भर्तियां होंगी। पहले भी यह स्थिति थी, अभी भी वही स्थिति रहेगी। इसका कड़ाई से पालन हो, इसकी मॉनिटरिंग होगी। वहीं उन्होंने किसानों के दो साल के बकाया बोनस पर कहा कि जो केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, वह इतनी कम है, इसके बारे में रमन सिंह पहले बताएं। हम तो लगातार किसानों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं. उन्होंने रमन सिंह के बयान पर कहा कि एकाध सलाह मोदी को भी दे दें। वहीं मंत्रियों के रायपुर में रहने पर बयान पर कहा कि रमन सिंह क्यों अपने घर मे कैद हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, पीएचई मंत्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्य सचिव आरपी मण्डल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुब्रत साहू, स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बेटियों की उपलब्धियों पर गौरव की होती है अनुभूति : गोकुलेश

जागरण
कला एवं संस्कृति

विन्ध्य का अभिनय के क्षेत्र में बढ़ेगा सम्मान यहां की कला,संस्कृति को मिलनी चाहिये पहचान

जागरण,सीधी

एण्ड टीवी सीरियल में हप्पू की उलटन-पलटन में देशभर में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली,विंध्य गौरव सुप्रसिद्ध अभिनेत्री,अदाकारा विन्ध्य की बेटी बहन कामना पाठक को इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड फॉर बेस्ट महिला हास्य कलाकार में शामिल होने बात सुनकार अपार खुशी हुई। उक्त बातें युवा विचारक एवं समाज सेवी गोकुलेश पाण्डेय ने जागरण से चर्चा करते हुये कही। गोकुलेश पाण्डेय काफी दिनों से दिल्ली में रहकर विन्ध्य का परचम लहरा रहें है और अपने विन्ध्य की कला एवं संस्कृति से निरंतर जुड़े रहते है। श्री पाण्डेय ने आगे कहा कि कामना बहन अभिनय के क्षेत्र में सफलता के उच्च आयाम स्थापित कर चुकीं है फिर भी अपनी संस्कृति, संस्कार, बघेली भाषा और विंध्य की माटी से आत्मीय और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। संभवत: यही कारण है कि यहां के लोग भी उन्हें उतना ही प्यार देते हैं । जीवन एक संग्राम की तरह है और जिसमें हमारी जय-पराजय काफी हद तक घर-परिवार गांव और परिवेश और आसपास के लोगों के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है यहां तक कि किसी की सफलता और असफलता में इन सब की सहभागिता भी होती है। इस दृष्टि से कामना जी की यह उपलब्धि हम सबको गौरवानुभूति का अवसर भी प्रदान करती है। सबसे खास बात यह है कि जब कोरोना काल में अच्छे समाचारों का अकाल सा पड़ गया हो ऐसे समय में उनके नॉमिनेशन की खबर से हम सभी प्रसन्न हैं। हमारी यह खुशी दुगुनी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बार एक- एक बेटी ने विंध्यवा सियों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। श्री पाण्डेय बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहीं हैं। देश की पहली महिला जेटफाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी के बाद सीधी और विन्ध्य के लिए यह दूसरा ऐसा अवसर है जब किसी बेटी ने हमारे मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की सबसे छोटी लोक गायिका बाल कलाकार मान्या पाण्डेय को पसंद किया जा रहा है उससे समूचे विन्ध्य को भी इनसे आशान्वित है। सफलता के शुभग शिखरों पर आरूढ़ होकर भी अपने गांव परिवेश और वहां के लोगों से प्यार करने वाली इस बेटी को अपनी क्षमतानुसार भावनात्मक सहयोग और समर्थन देना हम सबका कर्तव्य है। आईकॉनिक अवॉर्ड फार बेस्ट फीमेल एक्टर की यात्रा में वो विजेता बनकर कैसे उभरें। इस दिशा में भी प्रयास आवश्यक है। जो लोग उनकी इस सफलता से अपने आप को जोड़ना चाहते है। वो इंस्टाग्राम पर जाकर उनके पक्ष में अधिक से अधिक वोट करें । उन्होंने आगे कहा कि जिस माटी और परिवेश में वो पली-बढ़ी वहां की भीनी खुशबू बाकी लोगों का प्रेम अपनापन और वह भावना जो अपनी माटी में पनपे एक बीज को विशाल वृक्ष बनता देखना चाहती है उनके साथ है। उन्होंने कहा कि मेरी अनेक शुभकामनाएं जहां समूचा विश्व कोरोना से भयभीत है वहीं विन्ध्य की इस बेटी ने हमें प्रसन्नता और आत्म गौरव था स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है।

विन्ध्य का गौरव हैं कामना पाठक : डॉ. उत्तम

विन्ध्य की बेटी हप्पू की उलटन पलटन सीरियल में अपने अभिनय से देश में विन्ध्य का नाम रोशन करने वाली बेटी कामना पाठक इंटरनेशनल आइकॉनिक अवॉर्ड सीजन-6 में बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल, कॉमेडी के लिए नॉमिनेट की गई है। उक्त बातें जागरण से चर्चा करते हुये रीवा इंजिनियरिंग कालेज में प्रोफेसर डॉ उत्तम द्विवेदी ने कहा कि सीरियल में राजेश का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। कामना को बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का खिताब हमारे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिये दिए वोट से लेना है। विंध्यवासियो के लिए ये एक ऐसा अवसर है जिसके जरिये हम विंध्य को कला जगत में भी एक नई पहचान दिला सकते है कामना की विजय विंध्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को न केवल आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी कई गुना बढ़ाने में मददगार साबित होगी युवाओं में ये विश्वास पैदा होगा कि यदि प्रतिभा है तो पुरूस्कार महानगर से निकलकर कला जगत के लिए अब तक लगभग अपरिचित माने जाने वाले विंध्य क्षेत्र में भी लाये जा सकते है इसलिए विंध्य के युवाओं को आगे लाने के लिए आइयें। हम सब एक जुट होकर कामना जी को वोट करें और खिताब विंध्य की झोली में लाने का संकल्प लें।

हम सबका सम्मान हैं कामना : डॉ अनूप

सीधी जिले के समाजसेवी एवं लोक कला एवं रंगमंच को हमेशा सहयोग करने वाले कला प्रेमी डॉ अनूप मिश्रा ने कहा कि यह हमारे जिले के लिए गौरव की बात है कि हमारे जिले जो कि इस समय सिंगरौली में की बेटी आज फिल्म जगत में अपना इतना बड़ा नाम और शोहरत हासिल कर ली है। हमने काफी सोचा ही नहीं था कि हास्य धारावाहिक हप्पू की उलटन पलटन में जो प्रमुख पात्र है वह हमारे जिले की बेटी होगी। जब से इस बात की जानकारी आम जनता तक पहुंची है कि कामना पाठक विन्ध्य की बेटी है तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ता वही हमारे विन्ध्य के लोक कलाकार,हास्य कलाकार, साहित्यकार,कवि,नाट्य कलाकार सब इस समय कामना बेटी की ही चर्चा कर रहें हैं। ऐसा लग रहा है कि विन्ध्य को कोई एक नवाब हीरा मिल गया हैं। आने वाले समयों में कामना पाठक से विन्ध्य का नाम देश में रोशन होगा।

12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी में संशोधन

केमिस्ट्री का पेपर 9 जून को होगा

जागरण, रीवा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा समय सारिणी में संसोधन किया है। कुछ प्रश्न पत्रों के समय में परिवर्तन किया गया है। केमेस्ट्री का जो पेपर पहले 16 जून को होना था, वह अब 9 जून को होगा। माशिमं ने संशोधित समय सारिणी जारी कर दी है। नई समय सारिणी के अनुसार मंगलवार 9 जून को सुबह 9 से 12 बजे तक केमिस्ट्री व दोपहर 2 से 5 बजे तक भूगोल का प्रश्न पत्र होगा। इसी तरह 10 जून शनिवार को 9 से 12 बजे तक बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी और दूसरी पाली में व्होकेशनल कोर्स का प्रथम प्रश्नपत्र आयोजित किया जाएगा। गुरुवार 11 जून को बायलॉजी, शुक्रवार 12 जून को सुबह की पाली में व्यावसायिक अर्थशास्त्र और दूसरी पाली में एनिमल हस्बेण्ड्री मिल्कट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एंड फिसरीज, शनिवार 13 जून को सुबह राजनीति शास्त्र और दूसरी पाली में शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, द्वितीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स और द्वितीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स, सोमवार 15 मार्च को सुबह हायर मेथमेटिक्स और दूसरी पाली में विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास एवं तृतीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसी तरह 16 जून मंगलवार को सुबह 9 से 12 बजे तक अर्थशास्त्र और 2 से 5 बजे तक क्रॉप प्रोडेक्शन एंड हर्टिकल्चर का प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा।

दिव्यांग छात्रों की संशोधित समय सारिणी : दिव्यांग छात्रों की परीक्षा का समय दोपहर 2 बज से शाम 5 बजे तक रखा गया है। मंगलवार 9 जून को हायर मेथमेटिक्स, भूगोल का प्रश्न पत्र होगा। बुधवार 10 जून को बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, गुरुवार को बायलॉजी, अर्थशास्त्र, शुक्रवार 12 जून को व्यावसायिक अर्थशास्त्र, एनिमल हास्बेण्ड्री, शनिवार को राजनीति शास्त्र, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, सोमवार 16 जून को केमिस्ट्री, भारतीय कला का इतिहास, समाज शास्त्र, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, इनवायरमेंट एजुकेशन के प्रश्नपत्र होंगे।

दशहरा और दीपावली की छुट्टियां होंगी कम, अब एक घंटे ज्यादा लगेंगे स्कूल

नीरज गौर, भोपाल। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। इसमें दशहरा-दीपावली व सर्दियों की छुट्टियां कम होगी। स्कूलों का समय एक घंटे ज्यादा किया गया है। इसके साथ ही दो प्री बोर्ड के बजाय एक प्री बोर्ड होगी। एक सितंबर के बाद नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ, तो विभाग पाठ्यक्रम कम कर देगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की जाती है। जबकि प्रायवेट स्कूल मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह से नवीन

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करते देते है। कोरोना वायरस के चलते मार्च के तीसरे सप्ताह से देशभर में लॉकडाउन घोषित कर दिया था। इससे अभी तक नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ ही मप्र में दिन-प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसे देखते ही विभाग ने नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया है। ब्लू प्रिंट तीन तिथियों को लेकर तैयार किया गया है। इसमें पंद्रह जुलाई, एक अगस्त व पंद्रह अगस्त शामिल है। इन तिथियों में तैयार किए गए ब्लू प्रिंट के आधार पर प्रदेश में कोरोना

एक सितंबर के बाद सत्र शुरू करने पर कम होगा पाठ्यक्रम

स्कूल शिक्षा विभाग पंद्रह अगस्त तक नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर देता है, तो ब्लू प्रिंट के आधार पर आगामी समय में सेशन लेट कर पूरा कोर्स कराया जाएगा। विभाग ने यह भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है कि एक सितंबर के बाद नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होता है, तो हर कक्षा का पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों का साफ कहना है कि एक सितंबर या उसके बाद सेशन शुरू करने पर पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना संभव नहीं है।

मरीजों की संख्या देखते हुए स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। सुबह दस से पांच बजे तक लगेंगे स्कूल : विभाग के तैयार किए गए ब्लू प्रिंट में सुबह व शाम को आधा-आधा घंटा बढ़ाया गया है। ■ शेष पृष्ठ 7 पर

ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेनिंग के प्रेशर से शिक्षक परेशान

स्मार्ट फोन नहीं दे रहा साथ, मोबाइल नेटवर्क खराब

रीवा। लॉकडाउन में स्कूलें बंद है तो स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों को मोबाइल पर ही क्लास लगाने के निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही आनलाइन प्रशिक्षण और दीक्षा एप डाउन लोड करने के लिए दबाव बना रहा है। शिक्षक छुट्टियों में भी इन सब के लिए परेशान होकर भटक रहे हैं। एप और आनलाइन व्यवस्था बेहतर काम नहीं कर रही है। इससे लागिन और पासवर्ड के लिए कम्प्यूटर सेंटरों के चक्कर काटना पड़ रहा है।

ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल, कॉलेज बंद है। कॉलेजों में तो सब कुछ शांत है, लेकिन स्कूल के शिक्षकों को हर दिन नया टास्क दिया जा रहा है। मोबाइल पर ही ग्रुप बनाने के साथ ही मीटिंग का दबाव भी आ रहा है। शिक्षकों के पास आनलाइन क्लास और मीटिंग के लिए एप डाउन लोड करने की क्षमता वाले मोबाइल भी नही है। ऐसे में नए नए एप डाउन लोड ही नहीं कर पा रहे हैं। उस पर अब नया आदेश आनलाइन ट्रेनिंग लेने का भी पहुंच गया है। दीक्षा एप डाउनलोड करने के साथ ही पंजीयन कराने का भी दबाव दिया जा रहा है। पंजीयन न कराने और प्रशिक्षण न लेने पर शिक्षकों के वेतन रोकने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। वेतन रोके जाने के अल्टीमेटम के बाद से अब शिक्षक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम्प्यूटर सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं।

मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की घोषणा

छात्र अपने ही शहर में दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा

घर पहुंचे स्टूडेंट्स को स्कूल को बताना होगा कि वे किस जिले में हैं, इसके बाद स्कूल सेंटर की व्यवस्था करेगा

जेएनएन, नई दिल्ली।

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के सेंटर से जुड़ी बड़ी राहत की घोषणा की। निशंक ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना संकट के कारण जो बच्चे अपने गृह प्रदेश चले गए हैं और अपने बोर्ड परीक्षा के सेंटर वाले जिले में नहीं हैं, ऐसे छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने स्कूल को जिले और करीब के सेंटर की जानकारी देनी होगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई 2020 के बीच आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री निशंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। निशंक ने कहा कि बच्चों की परेशानी को देखते हुए ये फैसला किया गया है। अब बच्चों को चाहिए कि वे जल्दी से जल्दी अपने स्कूल से सम्पर्क करके उन्हें अपने गृह जिले के बारे में यह बताएं कि आप वहीं रहकर बाकी के पेपर्स देना चाहते हैं। स्कूल और विभाग इसकी पूरी व्यवस्था करके जून के प्रथम सप्ताह तक बच्चों को सेंटर की जानकारी दे देंगे। कोरोना लॉकडाउन के कारण सीबीएसई ने 83 विषयों की परीक्षाएं रोक दी थीं। इसके बाद बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि इन 83 विषयों में से 29 विषयों की ही परीक्षाएं होंगी। ये वही विषय होंगे, जो अगली क्लास में जाने के लिए जरूरी हैं।

एडमिट कार्ड भी नहीं बदलेंगे

सीबीएसई के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि एडमिट कार्ड वही रहेंगे। कारण, अब अलग-अलग स्टूडेंट्स के अलग-अलग पेपर हैं और हर पेपर में स्टूडेंट्स की संख्या भी कम है। अधिकतर स्टूडेंट्स के हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव जैसे पेपर शेष रहे हैं। मेन स्ट्रीम के पेपर पूरे हो चुके हैं। वहीं, कॉमर्स साइड का एक पेपर बिजनेस स्टडीज का बचा है। होम साइंस, भूगोल और बायो टेक्नोलॉजी के साथ ही आईटी के कुछ पेपर हैं। ये ऐसे पेपर हैं, जिनमें स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती। उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर बाकी इंडिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, लिट्रेचर सहित विभिन्न मेन स्ट्रीम के पेपर हो चुके हैं।

फिजिकल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल

परीक्षा केंद्रों पर सीबीएसई कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाए। 12वीं के जो पेपर शेष रहे हैं, उनमें स्टूडेंट्स कम हैं। सीबीएसई की डेटशीट में भी यह कोशिश की गई है कि एक दिन एक ही विषय का पेपर हो। ऐसे में स्टूडेंट्स की संख्या कम होने पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए परीक्षा केन्द्र पर अन्य कक्षों में भी स्टूडेंटस को शिफ्ट किया जा सकता है।

मीडिया और आईटी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रारंभ

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि के प्रभारी कुलपति प्रो. संजय द्विवेदी ने सभी विभागाध्यक्षों एवं प्राध्यापकों के साथ बुधवार को ऑनलाइन बैठक की, जिसमें पूर्व में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मीडिया और आईटी के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले विद्यार्थी विवि के भोपाल, रीवा एवं खंडवा परिसर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रो. द्विवेदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी पाठ्यक्रमों की जानकारी के लिए परिसर में नहीं आ सकते, इसलिए अधिक से अधिक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को बताया निराधार

स्कूल के खाने में मिला कीड़ा, पालक महासंघ ने की शासन से शिकायत

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

सोशल मीडिया पर इन दिनों कोलार रोड स्थित शारदा विहार बोर्डिंग स्कूल के नाम से भोजन में कीड़े निकलने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो मप्र पालक महासंघ ने मीडिया को दिया है। महासंघ का आरोप है कि स्कूल में प्रत्येक बच्चे से डेढ लाख से अधिक सालाना फीस वसूलकर खराब खाना दिया जा रहा है। पालक महासंघ के मुताबिक उन्हें एक बच्चे के पैरेंट्स ने एक वीडियो भेजा है, जिसमें जली हुई रोटियां दिखाई दे रही है और सब्जी में मटर के दानों के अंदर कीड़े दिख रहे हैं। पालक संघ ने चेतावनी दी है कि इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे। वहीं स्कूल प्रबंधन ने इसे झूठा आरोप बताकर बदनाम करने की साजिश बताई है।

आंदोलन किया जाएगा

शारदा विहार स्कूल को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही है। बच्चों से मोटी फीस वसूलकर कीड़े वाला खाना दिया जा रहा है। कारवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा।

कमल विश्वकर्मा, अध्यक्ष, मप्र पालक महासंघ

बदनाम करने की साजिश

लॉकडाउन के समय एक भी स्टूडेंट स्कूल व हॉस्टल मे नहीं है। यह स्कूल को बदनाम करने की साजिश है

राजेश तिवारी, प्राचार्य, शारदा विहार स्कूल, कोलार रोड, भोपाल

कंटेनमेंट एरिया के 19 परीक्षा केंद्रों को बदलने की तैयारी

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग राजधानी के कंटेनमेंट एरिया में आने वाले 12वीं कक्षा के शेष पेपरों के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों को एहतियात के तौर पर बदलने तैयारी कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने ऐसे 19 स्कूलों की सूची भी तैयार की है जो भोपाल जिले में बनाए गए कंटेनमेंट एरिया में आते हैं। इन केंद्रों में बदलाव व व्यवस्थाओं को लेकर डीईओ ने डीईओ कार्यालय में संबंधित संकुल प्राचार्यों की गुरुवार को बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में कंटेनमेंट एरिया में आने वाले परीक्षा केंद्रों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रीय पालक महासंघ सहित कई अभिभावक संगठनों के अभियान को मिल रहा बेहतर रिस्पॉन्स

निजी स्कूलों की मनमानी: 1.20 लाख से अधिक पैरेंट्स ने ट्वीट और रि-ट्वीट कर फीस माफी का किया समर्थन

हरिभूमि न्यूज ▸▸ भोपाल

लॉकडाउन के बीच निजी स्कूलों की मनमानी और फीस माफी के आदेश पर अमल नहीं होने से नाराज राष्ट्रीय पालक महासंघ के साथ देशभर के कई अभिभावक संगठन भी अब खुलकर सामने आए हैं। तीन महीने की फीस माफी की मांग को लेकर मप्र पालक महासंघ सहित राष्ट्रीय पालक महासंघ, ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन व एनसीआर पैरेंट्स एसोसिएशन ने ट्वीटर पर तीन हैशटेग नो स्कूल नो फीस, वेव स्कूल फीस और सीएम हेल्प पैरेंट्स अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका समर्थन करते हुए देश भर में 1.20 लाख से अधिक पैरेंट्स ने इसे ट्वीट और रिट्वीट कर फीस माफी का समर्थन किया है। ट्वीट में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, डीएम को टैग किया गया है।

› प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और डीएम को किया टैग

बंद के समय की ट्यूशन फीस वसूलने की दी अनुमति

पैरेंट्स का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल-कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद हैं। इसके बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें इस बंद के समय की ट्यूशन फीस वसूलने की अनुमति दी है। अभी कई स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य एक्टीविटी की फीस वसूल रहे हैं।

सरकार का फैसला आने तक चलाएंगे अभियान

मप्र पालक महासंघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने बताया कि पैरेंट्स की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। कंपनियां वेतन काट रही हैं। पैरेंट्स फीस जमा करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार ने फीस वृद्धि पर रोक लगाकर स्कूलों को ट्यूशन फीस की छूट दे दी है, लेकिन यह काफी नहीं है। लॉकडाउन के दौरान की फीस पूरी तरह माफ होनी चाहिए। महासंघ के महासचिव प्रबोध पंड्या ने बताया कि जब तक फीस माफ करने पर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, तब तक पैरेंट्स लगातार अभियान चलाएंगे।

खानापूर्ति से नाराज बाल आयोग ने लिखा प्रमुख सचिव को पत्र

फीस को लेकर स्कूलों के खिलाफ आई 150 शिकायतें, विभाग ने सिर्फ दो को दिए नोटिस

शासन द्वारा स्कूलों की फीस समायोजन के आदेश के बाद भी कई निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों की लगभग 150 शिकायतें मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास पहुंची हैं। शिकायतों पर आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्यालय को भी पत्र लिखा है, लेकिन पत्र लिखने के लगभग एक हफ्ते होने के बाद भी विभाग शिकायतों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। आयोग की दो बार की अनुशंसा और फिर सख्ती दिखाने के बाद अब बुधवार को भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दो स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। ऐसे में मामूली कारवाई पर असंतोष जताते हुए आयोग ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सरकार के निर्देश न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कई स्कूल ट्यूशन फीस के साथ वार्षिक फीस जोड़कर वसूली कर रहे हैं।

कोरोना संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखने की तैयारियां शुरू

सीबीएसई: सिलेबस में 25% कटौती, ऑड ईवन फॉर्मूले पर आएंगे स्कूलों में स्टूडेंट्स!

हफ्ते में तीन दिन घर से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होंगी, शनिवार को लगेगा फुल डे, एक से दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकेंगे विद्यार्थी, स्कूलों में बनेंगे कई एंट्री पाइंट

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सीबीएसई) बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने और पढ़ाई के नुकसान को पूरा करने के लिए सीबीएसई स्कूलों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, इस सत्र में पहली से 12वीं तक के सिलेबस में 25 से 30 परसेंट तक कटौती की जा सकती है। वहीं स्टूडेंट्स स्कूलों में ऑड ईवन पैटर्न पर आएंगे। हर स्कूल में स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर (आईडी नंबर) के आधार पर ऑड-ईवन पैटर्न पर बुलाया जाएगा। इस तरह एक बच्चा हफ्ते में तीन दिन स्कूल आएगा, बाकी तीन दिन उसे घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होंगी।

होमवर्क की बजाए प्रिंटेड वर्कशीट मिलेगी

शनिवार को हाफ डे के बजाय फुल क्लासेस लगाई जाएंगी। फुल डे क्लास लगाने से 3 पीरियड बढ़ेंगे। यानी कुल 84 पीरियड एक्स्ट्रा मिलेंगे। कुछ स्कूल रविवार को भी क्लासेस लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। होमवर्क नोट की बजाय अब प्रिंटेड वर्कशीट दी जाएगी, जो समय बचेगा उसमें पढ़ाई होगी। एक सेक्शन के स्टूडेंट्स दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकेंगे। सिलेबस पूरा करने फेस्टिवल और विंटर वेकेशन की छुट्टियां कम की जाएंगी। स्कूलों में एक से ज्यादा एंट्री-एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे, ताकि एक ही समय भीड़ न हो। बैंचेस एक से डेढ़ फीट की दूरी पर रखेंगे। जहां पहले दो स्टूडेंट बैठते थे वहां अब एक बैठेगा, ताकि दूरी बनी रहे।

गाइडलाइन के बाद साफ होगी स्थिति

इस संबंध में अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। गाइडलाइन आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। **मीनू जोशी, रीजनल ऑफिसर, भोपाल**

एनएसयूआई ने मेडिकल एक्जाम के टाइम टेबल में बदलाव की मांग की

एनएसयूआई मध्यप्रदेश के मेडिकल विंग समन्वयक रवि परमार ने बताया कि मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा फिजियो थेरेपी, बीएमएलटी, बीओटी, बीएचआरटी, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस इन सभी कोर्सों की परीक्षाएं जून माह में आयोजित की गई है, जोकि किसी भी तरह संभव नहीं है, क्योंकि इस समय को कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि छात्र-छात्राओं को संक्रमण का खतरा है। परमार ने पत्र के माध्यम से बताया कि कई छात्र-छात्राएं अन्य राज्य और अन्य जिलों से हैं, जिनका इस समय आना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में परीक्षाएं करवाना छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा।

मांग नहीं मानी तो करेंगे प्रदर्शन

रवि परमार ने पत्र से कुलपति से निवेदन किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी टाइम टेबल को छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल निरस्त कर आयोजित परीक्षाओं की तिथि में बदलाव कर नवीन टाइम टेबल जारी करें। अगर टाइम टेबल में परिवर्तन नहीं किया गया तो एनएसयूआई द्वारा इसका विरोध किया जाएगा।

पूर्व सीएम दिग्विजय का पत्र

सीबीएसई की परीक्षाओं को छात्रों के निवास के पास स्कूल में कराएं

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सीबीएसई की परीक्षाओं को छात्रों के निवास के निकटतम स्कूल और ऑनलाइन कराने की मांग की है। जिससे छात्रों ज्यादा सफर करना नहीं पड़े। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में कोरोना संक्रमण का जिक्र करते हुए लिखा है कि इसका डर छात्रों के पालकों में बना हुआ है। अभी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी नहीं है, यदि ट्रांसपोर्ट शुरु भी होता है तो लंबे सफर से संक्रमण का खतरा रहेगा। इसलिए निकटतम स्कूल को ही छात्रों की परीक्षा कराई जाए। गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा की समय सारणी जारी होने के बाद अब परीक्षा केंद्र भी चिन्हित कर लिए गए हैं।

अब जून में नहीं खुल सकेंगे विद्यालय

ग्वालियर, न.सं.

मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी किए थे कि सभी शासकीय विद्यालय सात जून से अपने नियत समय पर खोले जाएंगे। विद्यालयों में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों आएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब यह विद्यालय जून नहीं बल्कि जुलाई में खुल सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हायर सेकेण्ड्री की परीक्षाएं नौ जून से हो रही हैं। यह परीक्षाएं दो चरणों में होंगी, ऐसी दशा में विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो सकेगी। वहीं शहर में पड़ रही भीषण गर्मी एवं बढ़ते कोरोना वायरस के कारण विद्यालय जुलाई के प्रथम सप्ताह में खुलेंगे। शिक्षा विभाग के सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि अगर जुलाई में भी कोरोना का संक्रमण रहा तो विद्यालय अगस्त व सितम्बर में खोले जाने की योजना है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बच्चों को एक दिन छोड़कर विद्यालय बुलाया जाएगा, जिससे बच्चे दूर-दूर बैठकर पढ़ भी सकेंगे और कोरोना संक्रमण से दूर रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि बच्चों को मास्क लगाकर और ग्लब्स पहनकर विद्यालय आना होगा। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए रविवार को भी अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। साथ ही दशहरा, दीपावली और बड़े दिन के अवकाशों में भी कमी की जाएगी।

तालाबंदी खत्म होते ही दस्तावेजों का होगा सत्यापन

भोपाल

सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की आस में हजारों पात्र अभ्यर्थी दो साल से इंतजार कर रहे हैं। अभी तक तो शासन से अनुमति न मिलने से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। डेढ़ साल बाद जैसे-तैसे भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो तालाबंदी ने सपनों पर पानी फेर दिया। इस सत्र से पढ़ाने का सपना देख रहे भावी शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

सरकारी स्कूलों में जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 20,670 उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। दस्तावेज अपलोड भी कर दिए गए, लेकिन सत्यापन नहीं हो पाया। विभाग का कहना है कि जून से सत्यापन कार्य शुरू होने की संभावना है। इसके बाद इन शिक्षकों को नए मॉड्यूल के तहत जुलाई महीने में एक माह के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अगस्त से स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने लगेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी ने बताया कि तालाबंदी खत्म होते ही दस्तावेजों का सत्यापन का काम शुरू कर दिया जाएगा। जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन के बाद विभाग अंतिम चयन सूची व प्रतिक्षा सूची जारी होगी। ज्ञात हो कि 2018 से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार

स्कूल शिक्षा विभाग ने नव नियुक्त शिक्षकों को दिल्ली की तर्ज पर प्रशिक्षण देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। विभाग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार किया है। इन्हें स्कूल में पढ़ाने जाने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इनकी अपनी बात

“ उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तालाबंदी के कारण रुक गई है। जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। दस्तावेजों का सत्यापन होना है। यह प्रक्रिया तालाबंदी के बाद ही शुरू होगी।

गौतम सिंह, संचालक, डीपीआई

जीवाजी विवि ने आंतरिक व रुके हुए कामों को गति देने के लिए उठाया कदम

65 दिन बाद खुलेगा विवि, 50 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे, छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित

प्रतिदिन कार्यालय होंगे सेनेटाइज्ड, आरोग्य सेतु एप करना होगा डाउनलोड

ग्वालियर, न.सं.

अदृश्य महामारी कोविड-19 की वजह से शैक्षणिक संस्थानों पर ताले पड़े हुए हैं और सभी गतिविधियां बंद है। चौथे चरण के लॉकडाउन में कुछ राहत दी गई, जिससे अब आम जनजीवन सामान्य होने लगा है। करीब 65 दिन बाद जीवाजी विश्वविद्यालय की गतिविधियां भी गुरुवार से शुरू हो रहीं हैं। विवि प्रशासन ने परीक्षाओं व रुके हुए कामों को देखते हुए 50 कर्मचारियों को काम पर बुलाया है। छात्रों व बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अभी छात्रों की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। कर्मचारियों को सामाजिक दूरी के साथ-साथ कोरोना के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च को लगाए गए जनता कर्फ्यू के बाद से जीवाजी विवि सहित अंचल के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। चूंकि विश्वविद्यालय में यही समय परीक्षाओं का

रहता है इसलिए यह गतिविधि पूरी तरह बंद हो गई। हालांकि विवि के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षाओं के संबंध में दिशा-निर्देश देते रहे। अब विवि के सामने एक साथ करीब दो लाख छात्रों की परीक्षाएं कराना बड़ी चुनौती है। इसलिए विवि प्रशासन ने गुरुवार से विवि की गतिविधियां शुरू करने का निर्णय लिया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही काम होगा। रोटेशन के अनुसार 50 प्रतिशत कर्मचारी काम पर आएंगे और बाकि दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। सभी विभागों के अधिकारियों को एक साथ बुलाया है। विवि ने तय किया है कि जो कर्मचारी आएंगे वे रुके हुए व परीक्षा संबंधी कामों को पहली प्राथमिकता के साथ निपटाएंगे, ताकि शासन व राजभवन से जारी दिशा-निर्देशों के तहत परीक्षाएं कराई जा सके। कुलसचिव प्रो. आनंद मिश्रा द्वारा जारी आदेश में विशेष रूप से कर्मचारियों से कहा गया है कि वह मास्क लगाकर आएं और सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें। कर्मचारियों के आने से पहले कार्यालयों को सेनेटाइज करवाया जाएगा।

यह जारी किए दिशा-निर्देश

- कार्यालय का सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगा।
- समस्त विभागों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी।
- प्रत्येक कार्यालय को नियमित रूप से सेनेटाइज किया जाए।
- अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
- सामाजिक दूरी का पालन व मास्क लगाकर आना होगा।

कुलसचिव के निर्देश, परीक्षाओं की तैयारी में जुटें महाविद्यालय

विवि के कुलसचिव प्रो. आनंद मिश्रा ने बुधवार को अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शासन ने परीक्षाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। इसलिए महाविद्यालय तैयारियों में जुट जाएं। परीक्षा के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं करनी है वह समय से पहले पूरा कर लें। विवि से संबद्ध सभी 411 निजी व शासकीय महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जाएगा। ताकि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए यहां पर परीक्षाएं कराई जा सकें।

इनका कहना है

"पिछले तीन महीने से विवि की गतिविधियां बंद है, इस वजह से काफी काम पेंडिंग हो गया है। विवि के आंतरिक कार्यों व परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में अधिकारी-कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा रहा है। 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय आएंगे और कोरोना वायरस के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। बाहरी लोगों व छात्रों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।"

प्रो. आनंद मिश्रा
कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय